शुगर इंडस्ट्री को फायदा, किसान पसोपेश में

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सरकार द्वारा चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने की दिशा में की गई पहल को चीनी मिलों के संगठन इस्मा ने एक अहम फैसला बताया है। कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को बाजार भाव पर चीनी मिलों को बिक्री की स्वतंत्रता देने और लेवी शुगर की बाध्यता समाप्त करने का फैसला किया है।

इस्मा के महानिदेशक अबिनाश वर्मा का कहना है कि लेवी चीनी की बाध्यता हटने से इंडस्ट्री को सालाना 3,000 करोड़ रुपयें की बचत होगी। साथ ही कैबिनेट के इस फैसले से इंडस्ट्री को सालाना 20-25 फीसदी की ग्रोथ हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला रंगराजन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप है। इंडस्ट्री को काफी समय से इस कदम की प्रतीक्षा थी। इस फैसले ने उत्पादन लागत में कमी आएगी और चीनी मिलों के पास पूंजी की उपलब्धता बढ़ेगी। जिससे गन्ना किसानों को उनकी उपज का उचित और समय

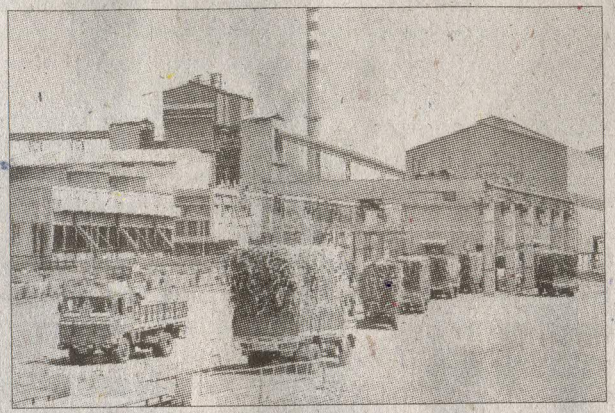

पर भुगतान करना सुनिश्चित हो सकेगा। इसके साथ ही चीनी मिलें उपभोक्ताओं को वाजिब दरों पर बेहतर गुणवत्ता वाली चीनी उपलब्ध करा सकेंगी।

इस्मा का कहना है कि रिलीज मैकेनिज्म को नियंत्रण मुक्त करने और लेवी शुगर की बाध्यता हटने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने के साथ-साथ गन्ने की पैदावार और चीनी उत्पादन के चक्र को भी व्यवस्थित किया जा सकेगा। कैबिनेट के इन दोनों महत्वपूर्ण फैसलों से किसानों और चीनी मिलों की क्षमता में सुधार आएगा और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय चीनी प्रतिस्पर्धी हो सकेगी। सरकार के इस कदम से देश का चीनी उद्योग निवेश के लिए काफी आकर्षक हो जाएगा। इस सेक्टर में बड़े निवेश आएंगे और इस सेक्टर पर निवेशकों और उद्यमियों का भरोसा बढ़ेगा। इस कदम से विदेशी निवेश भी आएंगे। इस कदम से उद्योग की क्षमता में सुधार होगा। इसका लाभ किसानों के साथ उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।

एसोसिएशन का मानना है कि वर्षों पुराने इस नियम को बदला जाना एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसका लाभ सबको मिलेगा। सहकारी चीनी मिलों के राष्ट्रीय महासंघ के प्रबंध निदेशक विनय कुमार का कहना है कि चीनी उद्योग के हित में यह ऐतिहासिक फैसला है। इससे उपभोक्ताओं और किसानों को भी राहत मिलेगी। अब 10 फीसदी चीनी सरकार को सस्ते दाम पर देने की बाध्यता नहीं रही। यह चीनी खुले बाजार में आएगी तो दाम कम हो सकते हैं।

चीनी शेयर उछले

मुंबई। शेयर बाजार में तगड़ी गिरावट के बावजूद चीनी पर सरकारी नियंत्रण हटने की आहट से चीनी कंपनियों के शेयरों ने तेजी की दौड़ लगाई। बजाज हिंदुस्तान 7.3 फीसदी बढ़कर 21.30 रुपये पर बंद हुआ। श्रीरेणुका शुगर्स 7.07 फीसदी उछलकर 25 रुपये पर बंद हुआ, बलरामपुर 4.02 फीसदी बढ़कर 47.85 रुपये पर बंद हुआ।

किस पर क्या होगा असर

चीनी मिल

- मिल को अभी अपनी दस फीसदी चीनी 19.05 रुपये किलो के भाव पर सरकार को पीडीएस के लिए देनी पड़ती थी। यह पाबंदी हटने से मिलों को करीब 3 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा।
- पाबंदियां कम होने से उद्योग को विकसित होने में मदद मिलेगी।

उपभोक्ता

- सरकार पर करीब 5300 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी का बोझ पड़ेगा। इसे कम करने के लिए राशन की चीनी के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। फिलहाल राशन की चीनी 13.5 रुपये किलो ही मिलती रहेगी।

चीनी मिल मालिक हमेशा लेवी कोटे की पाबंदी का रोना रोते थे। अब देखना है कि सरकार ने जो 3 हजार करोड़ रुपये की राहत मिलों को दी है, उसका कितना हिस्सा किसानों तक पहुंचता है। कम से कम अब मिलों के पास भुगतान में देरी के लिए लेवी कोटे का बहाना नहीं रहा। - **राकेश टिकैत**, प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन

रंगराजन समिति की सिफारिशों पर आधारित चीनी को नियंत्रण मुक्त करने का फैसला चीनी मिलों के पक्ष में है। चीनी के लिए जब रिलीज आर्डर नहीं होंगे तब खास तौर पर त्योहारों के समय चीनी मिलें मनमानी करेंगी और अपना कार्टल बना लेंगी जिससे चीनी की कीमतें बढ़ेंगी और खामियाजा आम उपभोक्ता को उठाना पड़ेगा। इसी तरह अगर कच्ची चीनी का सस्ता आयात खुला तो वे चीनी बनाने के लिए कच्ची चीनी का आयात कर सकती हैं और किसानों के गन्ना खेत में ही खड़े रहेंगे। - **वीएम सिंह**, संयोजक, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन

अमर उजाला
5/4/13